दैनिक जागरण 17-4-16
P-11

सफलता के सूत्र

सीआइआइ का अगले चार वर्षों में 30 करोड़ नौकरियां देने का सुझाव मुख्य रूप से निर्माण उद्योग में दिहाड़ी मजदूर की जरूरत पर आधारित है। वास्तव में यह विकास नहीं है। इसलिए यहां कुछ ऐसे आर्थिक उपायों के संबंध में सुझाव हैं जिनके दम पर एक बार फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा :

1 प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चूंकि बड़ी संख्या में आबादी कृषि से जुड़ी है तो ऐसे में खेती-बाड़ी को बेहतर आर्थिक संसाधन के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। इसके लिए ग्रामीण आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए अपेक्षित वित्तीय सहयोग की जरूरत होगी। इसके साथ ही व्यवस्थित तरीके से मंडियों के नेटवर्क को विकसित करने, ग्रामीण गोदाम और सिंचाई के साधन विकसित करने के लिए अधिक संसाधन की दरकार होगी।

2 जैसा कि पूर्व राष्ट्रपति डॉ अब्दुल कलाम ने सुझाया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं पहुंचाई जानी चाहिए। शिक्षण संस्थाएं, कॉलेज, अस्पताल के साथ गांवों और ब्लॉक स्तर पर एग्रो-आधारित उद्योगों को विकसित करने से ग्रामीण क्षेत्रों के भीतर ही रोजगार सृजित होंगे। इससे शहरी क्षेत्रों की तरफ पलायन में तेजी से कमी आएगी।

3 खाद्य सुरक्षा के लिहाज से गांवों को आत्म-निर्भर बनाने की दरकार है। इसके लिए खाद्य सुरक्षा कानून के प्रावधानों को किसानी व्यवस्था के साथ सम्मिश्रण की दरकार होगी। ब्लॉक या तहसील के स्तर पर गांवों के प्रत्येक संकुल को स्थानीय स्तर पर उत्पादन, प्रसंस्करण और वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

मेरा मानना है कि महात्मा गांधी भी इस योजना का समर्थन करते। दरअसल हमें 6.4 लाख स्मार्ट गांवों की जरूरत है और यदि हम टिकाऊ जीने लायक दशाएं बनाते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां शाश्वत रूप से हमारे प्रति कृतज्ञ रहेंगी।

17/4/16
प्रभारी, समाचार पत्र यूनिट